संपादकीय

जीडीपी में मज़बूत बढ़ोतरी से आत्ममुग्ध न हों

ऐसे वक्त में जब अमेरिका-ईरान युद्ध से कच्चे तेल के दामों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई और आपूर्ति श्रृंखला बाधित रही, देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती का संकेत सुखद ही कहा जायेगा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद दर 7.8 रही है। यह प्रदर्शन केंद्रीय बैंक आरबीआई के सात फीसदी की विकास दर के अनुमान से भी अधिक है। यह दर बाजार की उम्मीदों से भी अधिक है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष, ऊर्जा बाजार में उतार-चढ़ाव और ग्लोबल अनिश्चितता के बावजूद देश सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में शुमार है। दरअसल, इस तेज विकास दर को पाने हेतु विभिन्न क्षेत्रों में बेहतर प्रदर्शन से मदद मिली है। वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही में सेवा क्षेत्र में दस फीसदी की विकास दर उत्साहजनक रही है। विनिर्माण क्षेत्र में 9.2 तथा निर्माण क्षेत्र में विकास दर 7.7 फीसदी की वृद्धि ने देश की आर्थिकी को गति दी है। दरअसल, औद्योगिक विकास ने भी सकल विकास दर को संबल दिया। इससे भारतीय घरेलू अर्थव्यवस्था के महत्व का पता चलता है। उल्लेखनीय है इस दौरान देश में उपभोक्ता मांग अच्छी बनी रही। वास्तव में देश के बड़े उपभोक्ता बाजार ने वैश्विक मांग और व्यापार में आई शिथिलता के बावजूद स्वदेशी आर्थिकी को मजबूती दी है। भले ही देश का विपक्ष इस कामयाबी को आंकड़ों की बाजीगरी बता रहा है लेकिन सरकार इस उपलब्धि पर अपनी पीठ थपथपा सकती है। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि वैश्विक स्तर पर जारी अस्थिरता के चलते भविष्य में पैदा होने वाले जोखिम कम नहीं हो जाते हैं। विकास दर के इन आंकड़ों के चलते हमें लापरवाह होने से बचना चाहिए। पूंजीगत सामान के ज्यादा उत्पादन व सरकारी पूंजीगत व्यय में वृद्धि से पता चलता है कि देश में संरचनात्मक विकास व निवेश की मांग बनी हुई है। वास्तव में देश के नीति-नियंताओं को हमारी खाद्य श्रृंखला को मजबूती देने वाले और महंगाई को प्रभावित करने वाले कृषि उत्पादन में तेजी लाने की जरूरत है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के बीच इस बार देश के विभिन्न क्षेत्रों में हुई असमान बारिश का असर भी कृषि उत्पादन पर पड़ सकता है। देश का कृषि क्षेत्र अभी भी मौसम की मार के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। बहरहाल, पहली तिमाही के उत्साहवर्धक आंकड़े देश की वार्षिक विकास की अनुमानित दर में संशोधन करने की जरूरत को बताते हैं। यदि देश में घरेलू मांग और निवेश मजबूत बने रहते हैं तो हमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वार्षिक विकास दर का 6.7 फीसदी का अनुमान कम लग सकता है। इसके बावजूद, एक अच्छे तिमाही नतीजों का मतलब यह नहीं है कि आसन्न जोखिम से पूरी तरह बचा जा सकता है। ध्यान रहे कि 7.8 फीसदी की विकास दर पिछली तिमाही की 8.6 फीसदी की वृद्धि दर के मुकाबले थोड़ा कम है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में जारी अनिश्चितताएं अभी बड़ी चुनौती बनी हुई हैं।

विनोद शर्मा, संपादक

नीट परीक्षा के आयोजन में मौजूद बुनियादी खामियां

एक दिलचस्प ज़िक्र में, हैरान कविवर ने ऐसे छात्रों की तुलना हनुमान से की थी, जो लक्ष्मण की जान बचाने वाली खास जड़ी-बूटी लाने की बजाय पूरा पहाड़ ही उठा लाए थे। आज़ादी के बाद वाले काल में और डिजिटल दौर से पहले, परीक्षा से जुड़ी कई अन्य किस्म की धांधलियां सामने आईं। एक थी, 'परीक्षा केंद्रों की बिक्री', जहां उम्मीदवार आसानी से सीधे पाठ्यपुस्तक या उसकी 'कुंजी' (सवालों के हल आसान तरीके से समझाने वाली पुस्तिका) जैसे भरोसेमंद स्रोतों से जवाब नकल कर लिख देते थे। 'नीलाम किए गए' ऐसे कुछ परीक्षा केंद्रों में वे लोग भी मदद के लिए होते थे, जो ब्लैकबोर्ड पर सही जवाब लिख देते थे। वहीं कुछ जगहों पर छद्म परीक्षार्थी (असली उम्मीदवार की जगह परीक्षा देने वाले) की सुविधा भी मिलती थी।

नीट परीक्षा के पेपर लीक जैसी घटनाएं सिस्टम की कार्यक्षमता में नहीं, बल्कि उसके नैतिक चरित्र में आए संकट को दर्शाती हैं। वहीं नीट की एक बड़ी समस्या मल्टीपल-च्वायस क्वेश्चन (एमसीक्यू) आधारित चयन प्रणाली है। बेशक यह मशीनी आकलन में फिट बैठती हो, लेकिन मेडिकल शिक्षा के लिए जरूरी गुणों का सही आकलन नहीं करती। यह कोचिंग को बढ़ावा देती है। नीट (नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट) के साथ समस्या सिर्फ़ इसके पेपर लीक होने की प्रवृत्ति नहीं है। इससे भी बड़ी समस्या यह है कि इसके काम का तरीका बहुत अपरिष्कृत है। इसके लिए जो ऊंचा लक्ष्य रखा गया है, वह इसके अंदरूनी पुराने तौर-तरीकों से मेल नहीं खाता। नीट का मकसद लाखों लोगों में से उन्हें चुनना है, जो मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाने को सबसे योग्य हों। वास्तव में, इस मुश्किल काम को पूरा करने का तरीका बहुत सामान्य सा है। इसमें तीन विज्ञान विषयों–भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान–से 180 सवाल पूछे जाते हैं। ये सभी सवाल एक ही फॉर्मेट में होते हैं। हर सवाल के लिए चार संभावित जवाब दिए जाते हैं। उनमें से सिर्फ़ एक सही होता है। माना यह जाता है कि अगर छात्र होशियार है, तो वह तुरंत सही जवाब पहचान कर उसे चिह्नित कर देगा और अगले मल्टीपल-चॉइस क्वेश्चन (एमसीक्यू) पर बढ़ जाएगा। इसी फ़ॉर्मेट को एमसीक्यू कहते हैं। यह फ़ॉर्मेट भारतभर में इतना क्यों फैल गया है, यह एक ऐसा सवाल है, जिसका जवाब ढूंढ़ना वाजिब होगा। बैंकिंग से लेकर मेडिकल

कॉलेजों तक, लगभग हर क्षेत्र में अब शिक्षा और नौकरी के लिए उम्मीदवारों को चुनने के लिए एमसीक्यू सिस्टम का इस्तेमाल होता है। यह इतना पसंदीदा क्यों बन गया है। एक तो, एमसीक्यू के ज़रिए बड़े पैमाने पर परीक्षा लेना और तैयारी करवाना आसान होता है। कोचिंग उद्योग अब शिक्षा से भी बड़ा वित्तीय कारोबार बन गया है और इस उद्योग को एमसीक्यू बहुत भाता है। यह सिस्टम मशीनी तरीके से नंबरों का आकलन करने के लिए भी सुविधाजनक है। इस तरह की मार्किंग में निष्पक्षता दिखती है। पेपर लीक होने की घटनाओं को छोड़ दें, तो लोगों को सबसे ज़्यादा चिंता पक्षपात की होती है; इसलिए अगर कोई तरीका इस समस्या को दूर करता हो, तो उसकी लोकप्रियता कम करना मुश्किल होता है। असल में, एमसीक्यू-आधारित परीक्षा प्रक्रिया की मार्फत बड़ी संख्या में उम्मीदवारों की छंटाई कर उन्हें बाहर करना आसान बन जाता है। चूंकि बाहर किए जाने की यह प्रक्रिया मशीनी होती है और इसलिए निष्पक्ष बन जाती है। यही वजह है कि इस प्रक्रिया को वैध माना जाता है, भले ही यह पूरी सटीक न हो। वैधता और सटीकता के बीच का फ़र्क समझना ज़रूरी है। 'वैधता' का मतलब है लोगों की सोच में और कानूनी तौर पर सही उतरना। दूसरी ओर, 'सटीकता' का मतलब है परीक्षा के तरीके का उसके उद्देश्य से गहरा संबंध होना। नीट के खास संदर्भ में, कोई यह दावा नहीं कर सकता कि जो छात्र तेज़ी से भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के एमसीक्यू हल कर सकता है, उसमें एक अच्छा डॉक्टर बनने की क्षमता और योग्यता, दोनों हैं। नीट का काम बस बड़ी संख्या में आवेदकों को छांटकर अलग करना है। छंटनी के बाद बाहर हो चुके छात्रों में कितनों में डॉक्टर बनने के लिए ज़रूरी गुण और क्षमता थी, इसकी किसी को परवाह नहीं है। इस बात की भी कोई परवाह नहीं करता कि बाहर किए गए छात्र समाज के कमज़ोर वर्गों से थे या नहीं। ज़्यादातर मामलों में, नीट और ऐसे ही दूसरी परीक्षाओं में सफलता कोचिंग से जुड़ी होती है। कोचिंग पर उम्मीदवार और उनके माता-पिता का काफ़ी पैसा खर्च होता है। बहुत से छात्र किसी भी तरह की कोचिंग का खर्च नहीं उठा सकते, अच्छे और नामी कोचिंग सेंटर्स की तो बात ही छोड़ दें; ये सेंटर्स अपनी सफलता की दर, अपने कोच और वहां रहने-सहने की सुविधाओं के प्रचार-प्रसार पर बहुत पैसा खर्च करते हैं। अत्यंत व्यावसायिक हो चुकी इन सेवाओं ने स्कूलों और शिक्षकों को अप्रासंगिक बना दिया है। नीट में हालिया पेपर लीक का मामला कोई इक्का-दुक्का घटना नहीं थी। असल में, यह इतना आम हो गया है कि अगर कोई परीक्षा बिना पेपर लीक हुए भी हो जाए, तब भी लोगों में शक बना रहता है। प्रश्नपत्र लीक होने से परीक्षा का मकसद ही खत्म हो जाता है; साथ ही, यह उस सामाजिक माहौल को भी खराब कर देता है, जिसमें युवा रहते हैं और परीक्षा में सफल होने के लिए जी-तोड़ मेहनत करते हैं। प्रश्नपत्र पेपर लीक होना कोई नई बात नहीं, और न ही यह धांधली का एकमात्र तरीका है, जिससे भारत की परीक्षा प्रणाली दरपेश है। धांधली का मुख्य तरीका पेपर लीक बनने से बहुत पहले, गलत ढंग से सफलता पाने की कहानियां आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में आम चर्चा का विषय हुआ करती थीं। सवाल हल करने में मदद करने वाली कोई भी सामग्री परीक्षा केंद्र में साथ ले जाना मना था, लेकिन यह चलन इतना आम था कि इसने रवींद्रनाथ टैगोर तक का ध्यान खींचा।

जब जलवायु घर छीन रही हो, कानून को छत बनना होगा

प्रो. आरके जैन अरिजीत

बाढ़ और कटाव से घर उजड़ते हैं, परिवारों का भविष्य भी बह जाता है; लेकिन कानून में उनके लिए कोई ठिकाना नहीं। भारत में जलवायु परिवर्तन अब भविष्य की चेतावनी नहीं, लाखों लोगों की वर्तमान त्रासदी है। 2024 में जलवायु संबंधी आपदाओं से 54 लाख आंतरिक विस्थापन दर्ज हुए–दक्षिण एशिया में सबसे अधिक। करीब दो-तिहाई बाढ़ से जुड़े थे। 2022 में यह आंकड़ा 25 लाख था। असम, सुंदरबन, ओडिशा और बिहार के नदी-तटीय इलाकों में परिवार हर साल घर, खेत और पहचान खो रहे हैं। फिर भी अब तक (2026) ऐसा कोई कानून नहीं, जो उन्हें 'जलवायु विस्थापित' मानकर अधिकार तय करे। आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 तत्काल राहत तक सीमित है; स्थायी पुनर्वास और मुआवजे का अधिकार कानून से बाहर है। नदी का पानी उतर जाए तो आदमी घर लौट सकता है, लेकिन कटाव जमीन निगल जाए तो लौटने को कुछ बचता नहीं। यही नदी-कटाव को बाढ़ से अधिक क्रूर बनाता है। ब्रह्मपुत्र 1950 के बाद से असम की 4.27 लाख हेक्टेयर जमीन निगल चुकी है। माजुली द्वीप 1970 के दशक में 1,250 वर्ग किलोमीटर था, जो अब 350-600 वर्ग किलोमीटर रह गया है। सरकारी आंकड़े 2014-24 के बीच 17,390 लोगों के विस्थापन की बात करते हैं, जबकि संसद में दिए जवाब 86 हजार से अधिक लोगों की भूमिहीनता बताते हैं। तटबंधों या सरकारी जमीन पर बसे परिवार 'अतिक्रमणकारी' कहलाते हैं। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 में राज्य जमीन ले तो मुआवजा है; नदी ले जाए तो न अधिग्रहण माना जाता है, न मुआवजा। सबसे गहरी चोट तब लगती है, जब जमीन का अस्तित्व मिट गया हो और उसी का कागज मांगकर इंसान को राहत से बाहर कर दिया जाए। संविधान का अनुच्छेद 21 जीवन, आजीविका और आश्रय का अधिकार देता है, लेकिन अदालतें भी इस संकट का व्यापक समाधान नहीं कर पाई हैं। गौहाटी उच्च न्यायालय ने कुछ मामलों में राहत दी है, पर व्यापक नीति नहीं बनी। असम की 2020 की पुनर्वास नीति 2023 में संशोधित/आंशिक रूप से वापस ली गई। पंद्रहवें वित्त आयोग ने कटाव प्रभावितों के लिए अलग फंड की सिफारिश की थी और 2024 में केंद्र ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए, मगर जमीनी पहुंच सीमित है। दस्तावेजों की शर्त उस परिवार के सामने है, जिसकी जमीन और कागज दोनों नदी में समा चुके हैं। उजड़ना केवल गांव छोड़ना नहीं है; यह आदमी को उसकी पुरानी पहचान से भी बेदखल कर देता है। सुंदरबन में बढ़ती लवणता खेती और मछली पालन खत्म कर रही है। खेत और पानी जब रोजी छीन लेते हैं, तो परिवार शहरों की ओर जाता है। वहां झुग्गियों में नई जिंदगी शुरू होती है–मगर अधिकारों के बिना। कोई राष्ट्रीय रजिस्टर, स्पष्ट नोडल एजेंसी नहीं है। 2022 का निजी सदस्य विधेयक–क्लाइमेट माइग्रेंट्स (प्रोटेक्शन एंड रिहैबिलिटेशन) बिल–संसद में आगे नहीं बढ़ सका। इस बीच जलवायु विस्थापन अस्थायी घटना नहीं, स्थायी और संरचनात्मक संकट बनता जा रहा है। व्यवस्था फिर भी उसे 'आपदा' की छोटी अवधि में बांधकर देख रही है। दुनिया के दूसरे हिस्सों में कानून ने बदलती जलवायु की आहट सुन ली है, लेकिन भारत में उजड़े लोगों की आवाज व्यवस्था की दीवारों से टकराकर लौट आती है। बांग्लादेश और फिजी ने जलवायु विस्थापितों को कानूनी पहचान देने की दिशा में कदम उठाए हैं। ऑस्ट्रेलिया-तुवालु समझौता बताता है कि जलवायु आवागमन को कानूनी ढांचे में जगह दी जा सकती है। भारत में कार्बन सेस और पर्यावरणीय जुर्माने से समर्पित फंड बनाने के प्रस्ताव हैं, लेकिन राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव है। जब बांध या हाईवे परियोजना से विस्थापित व्यक्ति को मुआवजा और पुनर्वास मिलता है, तो प्रकृति से उजड़े परिवार को क्यों नहीं? जमीन जाने का दर्द उसके कारण से कम नहीं होता। इस कानून-विहीनता का सबसे भारी बोझ उन्हीं पर पड़ता है, जो पहले ही गरीबी ढो रहे हैं। आदिवासी, दलित और गरीब किसान जलवायु विस्थापन के सबसे असुरक्षित शिकार हैं। उनके लिए जमीन केवल संपत्ति नहीं, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और पीढ़ियों की पहचान है। जमीन जाने के साथ बच्चों की पढ़ाई, रोजी और समुदाय से जुड़ाव टूटता है। उनकी आवाज संसद तक पहुंचना कठिन है। चुनावी घोषणापत्रों में जलवायु विस्थापन का उल्लेख नहीं के बराबर है और सरकारी सर्वेक्षणों में भी यह प्राथमिकता नहीं बन पाया। जब विस्थापितों को कानून कोई नाम नहीं देता, तो उनके अधिकारों की मांग भी अनसुनी रह जाती है। यह केवल प्रशासनिक कमी नहीं, संवैधानिक समानता का गंभीर प्रश्न है।

महापौर ने विद्यार्थियों को योजनाओं का लाभ लेने किया प्रेरित

रायचंद नागड़ा उत्कृष्ट विद्यालय में गूंजी कृष्ण भक्ति, विद्यार्थियों को मिली निशुल्क साइकिल

पीपुल्स प्रवक्ता, खण्डवा।

रायचंद नागड़ा उत्कृष्ट विद्यालय में राज्य शासन की निशुल्क साइकिल वितरण योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन कृष्ण जन्माष्टमी के संदर्भ में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि विधायक कंचन मुकेश तनवे रहीं, जबकि अध्यक्षता महापौर अमृता अमर यादव ने की।

समाजसेवी व प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि छात्र हमारे देश का एवं परिवार का भविष्य है, यदि छात्र छात्राएं पढ़ाई कर कर आगे बढ़ती है तो यह परिवार के साथ देश के विकास में भी सहयोगी बनती है, बच्चों की पढ़ाई को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार कई प्रकार की योजनाएं चलाकर बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रही है, प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव की सरकार के द्वारा अच्छी पढ़ाई हेतु बच्चों को लैपटॉप, दूर से आने वाले बच्चों को हजारों रुपए की साइकिल, स्कूली ड्रेस एवं पाठ्यपुस्तिकाओं का निशुल्क वितरण कर रही है।

जन्माष्टमी पर्व को लेकर भी प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा शासकीय रूप से धर्म और संस्कृति और अध्यात्म से युवा जुड़े रहे हैं इस हेतु जन्माष्टमी का पर्व मनाया जा रहा है स्कूलों में भी या आयोजन शुरू हो चुका है। समाजसेवी सुनील जैन ने बताया कि बुधवार को उत्कृष्ट विद्यालय में जन्माष्टमी पर्व एवं शासन की योजना अंतर्गत 17 छात्र-छात्राओं को निशुल्क साइकिल का वितरण महापौर, विधायक द्वारा किया गया। आयोजन के दौरान विद्यार्थियों को शासन की विद्यार्थी हितैषी योजनाओं की जानकारी देते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में महापौर अमृता अमर यादव ने विद्यार्थियों से कहा कि शासन द्वारा विद्यार्थियों के हित में अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

विद्यार्थी इन योजनाओं का लाभ लेकर अपने लक्ष्य के अनुरूप नियमित और अनुशासित ढंग से अध्ययन करें। महापौर ने कहा कि भगवान राम ने हमें मर्यादा से जीना सिखाया वही भगवान श्री कृष्ण ने गीता के माध्यम से जीवन जीने की कला सिखाई। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक कंचन मुकेश तनवे ने समय के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विद्यार्थियों को समय का सम्मान करते हुए अपनी पढ़ाई की योजना बनानी चाहिए।

लायन्स क्लब खण्डवा एवं सक्षम संस्था ने की नेत्रदान जागरूकता पखवाड़ा की शुरूआत

नेत्रदान जागरूकता के किये जा रहे विभिन्न आयोजन

पीपुल्स प्रवक्ता, खण्डवा।

जिला द्रष्टिविहीनता नियंत्रण समिति चेयरमेन व कलेक्टर ऋषव गुप्ता के मार्गदर्शन में सक्षम मालवा प्रान्त की सक्षम खण्डवा इकाई अध्यक्ष नारायण बाहेती सचिव रविन्द्र चौहान,संरक्षक सुरेंद्रसिंह सोलंकी, कोषाध्यक्ष राजीव शर्मा व लायन्स क्लब खण्डवा अध्यक्ष घनश्याम वाधवा सचिव हेमलता पालीवाल कोषाध्यक्ष पवन लाड़ जिला अंधत्व निवारण समिति की ओर से सीएमएचओ डॉ ओ पी जुगतावत, डॉ अनिरुद्ध कौशल,डॉ ओनकर,प्रहलाद तिरोले,अर्जुन वर्मा के नेतृत्व में नेत्रदान देहदान व अंगदान जनजाग्रति समिति खण्डवा द्वारा राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा 25 अगस्त से 8 सितम्बर तक मनाया जा रहा है। समिति संयोजक नारायण बाहेती ने बताया कि नेत्रदान पखवाड़े में विभिन्न स्थानों पर नेत्रदान जागरूकता कार्यक्रमो का आयोजन कर लोगो को नेत्रदान के प्रति जागरूक किया जा रहा है।जिला चिकित्सालय परिसर में नेत्रदान जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया

गया।21 लोगो ने नेत्रदान संकल्प पत्र भरे।समिति द्वारा भागवत कथाओं,बड़े आयोजनों, बेनर ,पोस्टर , नाटक,व पम्पलेट के माध्यम से समिति के नारायण बाहेती, डॉ सोमिल जैन, नेत्र सहायक प्रहलाद तिरोले,अनिल बाहेती, सुरेंद्रसिंह सोलंकी, डॉ राधेश्याम पटेल,घनश्याम वाधवा,राजीव शर्मा,राजीव मालवीय, सुनील जैन,गांधी प्रसाद गदले,रणवीर सिंघ चावला, चंचल गुप्ता,व सदस्यों द्वारा,जागरूकता कर अब तक 531 लोगो के मरणोपरांत नेत्रदान कर कार्निया आई बैंक भेजे गए जिससे सैकड़ो लोगो को रोशनी प्राप्त हुई।25 मृत देह भी मेडिकल कालेज को दान की गई।जागरूकता कार्यक्रम मे पदाधिकारियो के साथ ही अखिलेश गुप्ता,गांधीप्रसाद गदले, हेमलता पालीवाल, अरुण बाहेती ,महेश पेसवानी ,सुशीला गदले ने भी नेत्रदान की जानकारी दी।

सद्भावना मंच के आमने सामने कार्यक्रम में शामिल हुए केबीसी के प्रतियोगी

पीपुल्स प्रवक्ता, खंडवा

देश के सर्वाधिक लोकप्रिय,ज्ञानवर्धक और मनोरंजक धारावाहिक 'कौन बनेगा करोड़पति...' की हॉट सीट पर पहुंचना और सदी के शिखर अभिनेता सुपर स्टार अमिताभ बच्चन से रूबरू होकर धन राशि जीतना हर किसी का दिवा स्वप्न है, जिसका स्वप्न साकार हो जाए वह अपने आप को धन्य ही समझता है। यह बात सौमित्र नगर खंडवा के निवासी वीरेंद्र जायसवाल ने सद्भावना मंच के आमने-सामने कार्यक्रम में कही। सद्भावना मंच के सदस्य कमल नागपाल ने विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि मंच द्वारा संस्थापक प्रमोद जैन के मार्गदर्शन में विविध विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिभाओं को बुलाकर उनसे रूबरू हुआ जाता है और उन्हें सम्मानित किया जाता है।विगत दिनों खंडवा के प्रतिभावान प्रतियोगी वीरेंद्र जायसवाल केबीसी के कार्यक्रम में पहुंचे और 7,50,000 की धनराशि जीतकर खंडवा को गौरवान्वित किया।

महिला मोर्चा के रक्षाबंधन समारोह में जिला अध्यक्ष का हुआ अभिनंदन

बड़ी संख्या में मातृशक्ति को जोड़कर महिला मोर्चे को और सशक्त करूंगी: श्रुति जैन

पीपुल्स प्रवक्ता, खण्डवा।

भाजपा महिला मोर्चा द्वारा जिला कार्यालय में रक्षाबंधन पर्व एवं पार्टी संगठन द्वारा अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी की महिला पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने उत्साह के साथ सहभागिता की। रक्षाबंधन के अवसर पर भाई-बहन के स्नेह और संगठनात्मक एकजुटता का संदेश भी दिया गया। प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि भाजपा संगठन में महिला मोर्चे की एक अहम भूमिका है, लगातार भाजपा संगठन में मातृशक्ति बड़ी संख्या में जुड़ रही है। भाजपा प्रदेश संगठन द्वारा पार्टी का वर्षों से कार्य कर रही श्रुति जैन को महिला मोर्चे का जिला अध्यक्ष की नियुक्त किया गया हें बुधवार को भाजपा कार्यालय में जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर की अध्यक्षता में अभिनंदन समारोह एवं रक्षाबंधन पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि इस अवसर पर नवनियुक्त जिला अध्यक्ष श्रुति जैन का स्वागत व सम्मान जिला अध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर प्रदेश महिला मोर्चे की मंत्री चारुलता मंगल यादव, महापौर अमृता अमर यादव खंडवा विधायक कंचन मुकेश तनवे उपस्थित मातृ शक्ति द्वारा किया जाकर उन्हें शुभकामना दी गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष श्रुति जैन ने कहा कि भाजपा प्रदेश एवं जिला संगठन ने जो मुझे दायित्व सोंपा है उस दायित्व का पूरी ईमानदारी के साथ आप सभी के सहयोग से निर्वहन कर बड़ी संख्या में महिलाओं को जोड़कर महिला मोर्चे को सशक्त करूंगी एवं पार्टी के कार्यक्रमों को लगातार सक्रियता के साथ संपन्न कराऊंगी। कार्यालय में जिला अध्यक्ष श्रुति जैन एवं मातृ शक्ति द्वारा रक्षाबंधन पर्व बनाकर जिला अध्यक्ष श्री तोमर की साथ ही अन्य भाइयों को रक्षा सूत्र बांधे गए। प्रवक्ता सुनील जैन ने बताया कि रक्षाबंधन एवं अभिनंदन कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष राजपाल सिंह तोमर, महिला मोर्चा प्रदेश मंत्री चारुलता यादव विधायक कंचन मुकेश तनवे, महापौर अमृता अमर यादव, पंधाना जनपद अध्यक्ष सुमित्रा काले, ओंकारेश्वर नगर परिषद अध्यक्ष मनीषा परिहार, जिला उपाध्यक्ष इंदु दुबे, महामंत्री संतोष सोनी, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सागर आरतनी, प्रवक्ता सुनील जैन, तिलोक पटेल, आशीष राजपूत, भारत पटेल अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र दागोरे, सहित पार्टी के पदाधिकारी उपस्थित रहे।

स्वामी, भाग्यमीडिया पब्लिकेशन प्रा. लि. के लिए प्रकाशक, मुद्रक राजेश शर्मा द्वारा प्रदेश वॉच मीडिया ग्रुप 11 प्रेस काम्पलेक्स जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) से मुद्रित कर, जी-11 प्रथम तल गोयल निकेत जोन-1 एम.पी. नगर भोपाल (म.प्र.) से प्रकाशित, पिन-462011, संपादक : विनोद शर्मा, फोन नं. 0755-4512708, पीआरबी एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार सभी मामलों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा। RNI No. MPHIN/2016/68059